[Shrimati Bijoya Chakravorty]

These ex-servicemen who had spent their days and nights in the hills and dales in difficult terrain braving all the odds while guarding our territories in different parts of the country, were deprived of their family life and comfort that we are enjoying in our day-to-day life. It is really difficult to accept that the just demands of these brave people go unheeded. Their demand is for rank-to-rank pension, pension to pre-1964 widows, restoration of commuted pension, employment up to 58 years of age and a policy for resettlement with self-employment schemes and vacation of lands and houses.

Madam, a committee was appointed on 28th February, 1984 to look into the problems of ex-servicemen. The high level committee under the adroit leadership of Shri K. P. Singh Deo produced a report making 68 recommendations, covering all aspects of ex-servicemen's problems and the report was submitted to an empowered committee for implementation. But the empowered committee scuttled all the substantive recommendations wherever there were financial implications. I want to cite one example here. Since January, 1985, 69 ex-servicemen employed in Army Group insurance were thrown out of job without showing any reason. The high level committee comprising nine Ministers from Central and the State Governments, five hon. Members of Parliament and five retired senior officers of the armed forces, made these recommendations after very serious deliberations and taking into consideration all the factors. But the bureaucrats are acting as stumbling blocks in the implementation of these recommendations.

I, therefore, urge upon the authority concerned to take immediate steps for acceptance of all the recommendations made by the high-level committee and to implement them urgently.

Thank you.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—contd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up further discussion on the Motion of Thanks on the President's Address.

Mr. Shanti Tyagi. He had not concluded his speech yesterday. He shall continue.

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra): He had just begun.

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : आदरणीया, आपने मुझे इस सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

माननीया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिन चीजों का उल्लेख है उनको मैं कहूंगा । उसमें उल्लेख है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति का, उसमें उल्लेख है कृषि, उद्योग, साइंस, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन आदि क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का, उसमें उल्लेख है अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की भूमिका का, उसमें जिक्र है देश में बढ़ते हुये धार्मिक कट्टरपन, साम्प्रदायिक उन्माद का, पंजाब के विघटनकारी राष्ट्रद्रोही आतंकवाद का और राज्य स्टेट के शासन में धर्म को हावी करने की कुचेष्टा का तथा इसकी पीठ ठोंकने वाली विदेशी, भारत विरोधी शक्तियों का । ये उल्लेख इसके अन्दर हैं ।

आदरणीय उपसभापति महोदया, पाकिस्तान द्वारा इस साल के जनवरी महीने में हमारी सरहदों पर अपने आक्रामक डिवीजनों की तैनाती से जो तनाव पैदा हुआ उसका उल्लेख भी इस अभिभाषण में है तथा हमारे देश में जो कमजोरियां हैं, सरकार की जो खामियां हैं उसका भी जिक्र है । अन्त में जो देश की बुनियादी नीतियां हैं, जो राष्ट्र के हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं और

हमारे भविष्य की जो दिशा है उसका उल्लेख करके यह भाषण समाप्त किया किया गया है ।

मुझे अफसोस है, आदरणीया, कि इन तमाम चीजों के वर्णन के बाद भी राष्ट्रपति के भाषण में विपक्ष के बहुत से सदस्यों को कुछ नजर नहीं आया । ऐसे विचार यहां आये और एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता हैं माननीय अटल जी उनको तो यही शिकायत रही कि भाषण बहुत लम्बा है। लम्बाई की शिकायत आई और एक भाई को यह भी ऐतराज हुआ कि हमारे राष्ट्रपति ने कम देशों की राजकीय यात्रा क्यों की और हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ज्यादा देशों की यात्रा पर क्यों चले गये। यह भी एक आब्जक्शन किया गया । आदरणीया, किसी विपक्ष के सदस्य ने कहा कि पिछले साल में जो घटनायें हुई हैं यह उनका कलेक्शन है, संकलन है । यह आब्जेक्शन किया गया, आपत्ति की गई और किसी ने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, गरीबी और बढ़ रही है, अमीरी और बढ़ रही है तथा देश में कुछ नहीं है ऐसे बहुत से विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस भाषण पर अपने विचार रखे ।

अन्त में यह बात भी की गई कि भाषण में हमारे देश के सामने जो मौजूदा काम हैं, जो जन समस्यायें हैं, बर्निंग प्राब्लम्स हैं उनका कोई इशारा नहीं किया गया है और भारत की सरकार की उन समस्याओं का समाधान करने की क्या दिशा है और क्या समाधान का विचार रखती है यह बात नहीं की गयी है । मैं यह कहूंगा कि यह बहुत ज्यादती की गई है । माननीय विपक्ष ने बहुत ज्यादती की है । आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं विपक्ष में रह चुका हूं । बहुत दिनों तीसियों साल से मैं आज आपसे कहता हूं कृपया एक बात विपक्ष मेरी मान लें, सत्ता की छोड़िये वह किसी को आये किसी को न आये बहुत बड़ी बात नहीं हैं यह मेरी बात मान लें . . . । कोई भी सरकार हो उसकी जो कामयाबियां, प्राप्तियां और उपलब्धियां हैं उनको आप कृपया स्वीकार कीजिये और जो खामियां हैं उनको आप बताइये तब आपकी साख आवाम में बनेगी। यह भूमिका विपक्ष की प्रतिदिन होनी चाहिये । क्या यह सही नहीं है कि जी० एन० पी० में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है, गत वर्ष हमारा फूड-ग्रेन का उत्पादन 15 करोड़ पांच लाख टन हुआ और 1987 में इससे ज्यादा या कमोबेश हम उतना उत्पादन करने जा रहे हैं । क्या यह बात सही नहीं है कि हमारे देश की सरकार के पास दो करोड़ छत्तीस लाख टन अनाज का रिजर्व भंडार है और हमने अपनी वितरण प्रणाली में अनाज की मात्रा को भी बढ़ा दिया है। क्या मैं अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से यह सवाल पूछ सकता हूं कि यह हमारे देश की जर्जर होती हुई अर्थ-व्यवस्था है या आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का सबूत है या गरीबी बढ़ रही है या अमीरी बढ़ रही है ? हम यह कहते हैं आदरणीय बन्धुओं आप इस देश के किसानों को इस उपलब्धि के लिए मुबारिकबाद दीजिये और सरकार की जितनी भी प्रगतिवादी कृषि नीतियां हैं उनकी आप सराहना कीजिये। हमारा देश जो पहले एक भूखा नंगा देश था और अमरीका से कभी सड़े गले अनाज की खैरात मांगता फिरता था आज स्वावलम्बी मुल्कों की कतार में खड़ा हो गया है और अनाज का निर्यात करने को भी तैयार है और निर्यात कर भी रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। इसको आप स्वीकार कीजिये। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि इंकमटेक्स, विदेशी-मुद्रा की चोरी करने वालों, उद्योगपतियों धन्ना सेठों और धन-कुबेरों के कार्यलयों तथा निवासों पर छापे डालना, उनको जेलों का मुंह दिखाना जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, कानून की गिरफ्त में अपराधियों को पकड़ना और खड़ा करना, क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह गरीबों की तरफदारी है या अमीरों की तरफदारी है ? क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार की जो नीति काला-धन पकड़ने की है या इनकम टैक्स चोरी को पकड़ने की है क्या यह अमीरों के पक्ष की नीति है या गरीबों के पक्ष की नीति है, यह जन-विरोधी नीति है या जनता के पक्ष की नीति है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आर्थिक क्षेत्र में हमारी जो गरीबी मिटाने की देहात में

[श्री शान्ति त्यागी]

योजनाएं चल रही हैं जैसे आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, यह हमारी प्रमुख योजनाएं है इन योजनाओं के लिए जो इस वर्ष प्रावधान किया गया है वह गत सालों की तुलना में बहुत ज्यादा है। आई० आर० डी० पी० के लिए 543.83 करोड़, एन० आर० ई० पी० के लिए 470.72 करोड़ और आर० एल० ई० जी० पी० के लिए 731.01 करोड़ का प्रावधान है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रोग्राम जो हैं देहात में जो सामली जमींदारी प्रथा के अवशेष जमींदार बैठे हुए हैं, जो अमीर किसान पैदा हो गया है यह तीनों प्रोग्राम जो हैं उनके पक्ष के हैं या देहात में गरीब और बीच के छोटे किसानों को उभारने वाले प्रोग्राम हैं। यह मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं आप कृपा करके इनका जरूर उत्तर दें जब आप इस चर्चा में भाग लें। मेरे विचार में हमारे जो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं उन्होंने सरकार की विदेश नीति की तारीफ की है इसके लिए मैं उनका आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम सरकार की विदेश नीति के बारे में तो सारे सदन की एक राय है। यह एक ऐसा समय है जब भारत का नाम समाजवादी देशों में, खास तौर से गुट निरपेक्ष देशों में विकासशील देशों में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। श्री गोर्बाचोव सोवियत नेता जब भारत आए तो उन्होंने यहां पर भारत में और अपने देश में भी कई दफा यह कहा है कि भारत आज दुनियां की मेजर वर्ल्ड पावर है। यह संज्ञा उन्होंने भारत को दी है। यह हमारे लिए कम गौरव की बात नहीं है। यह सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि हकीकत है, एक एकनालेजमेंट है। इस हकीकत को एक बड़ी पावर, सुपर-पावर के जरिए पहचानना है, उसकी शिनाख्त है।

इसलिए मैं कहता हूं कि क्या आपको गौरव नहीं होता, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका माथा क्या ऊपर नहीं उठता जब दो साल के मामूली अरसे में दो साल के छोटे से संक्षिप्त काल में देश के युवा प्रधान मंत्री का नाम दुनिया में, विश्व के बड़े नेताओं में शुमार होता है? कोई बात तो रही होगी, कोई उपलब्धि, कोई अचीवमेंट तो है। आपने भारत में आजादी के लिए स्वाधीनता के लिए, उपनिवेशवाद के खिलाफ, निओ.कालोनियलिज्म के खिलाफ और जो, रंगभेद सरकार है अफ्रीका की, उसके खिलाफ जो शांति के लिए आवाज बुलंद की है उसी का परिणाम है कि युवा प्रधान मंत्री का नाम विश्व नेताओं में दो ही साल के संक्षिप्त अरसे में शुमार किया जा रहा है। यह बड़ी बात है। हम सब को इसके ऊपर फख्र होना चाहिए।

अंत में, माननीया उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि सदन में भारत-पाकिस्तान संबंधों की भी चर्चा हुई है और वह हमेशा होती रही है। कभी एटम बम के निर्माण के संबंध में, और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने अपनी आक्रामक सेना हमारी सीमा पर जनवरी में खड़ी कर दी थी। अभी देश में और बहुत सी विघटनकारी शक्तियां काम कर रही थीं, उसी बीच यह तनाव भी पैदा हो गया। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज थी उनको भी अगली पंक्तियों में खड़ा होना पड़ा और वह जल्द और बड़े टाईम से खड़ी हो गई। अब तनाव को समाप्त करने की बातें तो कल-परसों ही खत्म हुई हैं। तनाव खत्म भी हो रहा है। जाहिर है कि फौजें वापस लौटेंगी इधर भी और उधर भी। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है।

महोदया, मैं भारत की सरकार को आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं और पूरे देश की जनता से भी कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के प्रेजीडेंट की नीयत, उनका दिल और उनका दिमाग भारत के प्रति साफ और सुथरा नहीं है। उनकी नीयत में खराबी है, यह मैं कहना चाहता हूं और उनके दिल में आज भी, चाहे एग्रीमेंट हो चुका फौजों की वापसी का और तनाव खत्म करने का, भारत के लिए उनके दिल में और दिमाग में दुश्मनी का जज्बा है, यह मैं कहना चाहता हूं और मुझे यह कहने में कोई

संकोच नहीं है और न कोई शर्म है। वह दोस्ती की, शांति की राह पर नहीं हैं, तनाव कम करने की राह पर नहीं हैं। वह अमरीकी हथियारों से अपने को, अपनी सेना को सजा रहा है और वह एटम बम के निर्माण के रास्ते पर, चाहे वह बना चुका है, या कल बनाने वाला हो, इस रास्ते पर चल रहा है।

इसलिए मैं कहता हूं कि भारत सरकार इस सदन को, देश की पूरी जनता को, तमाम डेमोक्रेटिक और पैट्रियाटिक फोर्सेज जो हैं, उनको विश्वास में ले और इस बात का ऐलान करे कि एक अणुबम वाला पाकिस्तान भी अगर हमसे लड़ने आएगा, तो हमारे पास यह ताकत रखी हुई है, जो उसको पस्त करेगी, पराजित करेगी और कभी भी हमारी तरफ वह कड़वी निगाह से आईन्दा न देखे। ऐसा इंतजाम हम करेंगे, ऐसी सामरिक व्यवस्था हम कर चुके हैं डिफेंस की और सुरक्षा की, इस नई व्यवस्था का ऐलान भारत सरकार करे। यह मेरी मांग है। —

अंत में बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे सदन ने मिल कर सभी पार्टियों ने देश में जो रिलीजियस और कम्यूनल फोर्सेज हैं, रिलीजियस मतलब जो कट्टरवाद की ताकतें हैं, देश को तोड़ने की ताकतें हैं, जो विदेशी नियंत्रण में काम कर रही हैं, विदेशी प्रेरणा से काम कर रही हैं, विदेशी ताकतें जो भारत विरोधी हैं, उनकी शह पर काम कर रही हैं, इन तमाम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है सदन में, हम सब को बहुत प्रसन्नता है।

प्रधान मंत्री जी के साथ बैठ कर भी तमाम विरोधी पक्ष के नेताओं और सभी नेताओं ने बैठ कर इस बात का संकल्प किया है कि पंजाब में धर्म को हम राजनीति के ऊपर हावी नहीं होने देंगे और भारत में मंदिरों से और मस्जिदों से तथा गुरुद्वारों से सरकार बर्खास्त करो और यह प्रधान मंत्री बर्खास्त करो, वह मुख्य मंत्री बर्खास्त करो, यह नीति, यह घोषणा, यह हुकमरानी फरमान अब बर्दाश्त नहीं किये जाएंगे, इस बात का संकल्प लिया सब नेताओं ने प्रधान मंत्री जी के साथ बैठ कर। मैं यह नहीं मानता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने पहली दफा विपक्ष के नेताओं को इस सवाल के ऊपर विश्वास में लिया हो, ऐसा नहीं है। हमेशा प्रधान मंत्री ने हमारी देशप्रेमी, जनवादी, समाजवादी और प्रगतिशील तमाम ताकतों से अपील की है कि वह आयें और संयुक्त रूप से इन विघटनकारी ताकतों के खिलाफ रिलीजियस फंडेमेंटेलिज्म के खिलाफ पंजाब में जो कुछ आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह है, उसके खिलाफ मुश्तरका जंग लड़ें, यह हमेशा प्रधान मंत्री की अपील रही है, आवाहन रहा है और प्रयास रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुन: धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और अब तो काफी बड़े नेता बैठे हैं विपक्ष के, मैं इन शब्दों के साथ खत्म करना चाहता हूं कि आइये, सब मिल कर देश बचायें, आइये, सब मिल कर देश बनायें। धन्यवाद।

SHRI SAMAR MUKHERJEE (West Bengal): Madam Deputy Chairman, the speech made by Rashtrapati is a long speech. When I was listening to his speech in the Joint Session, my reaction was, the weaker the case, the bigger the speech and that is a reality. Subsequently, when our Prime Minister placed the Budget—because Budget and his speech come under the same policy framework of the Government —I, saw the reaction of the 'Times of India' newspaper of 1st of March and I am quoting :

"What the Budget papers revealed is a book of gross mismanagement of the economy during the past year or more as well as an awkward attempt to cover up the loss of the Government's grip over it. The most distressing aspect of this is, of course, the huge Budgetary deficit of Rs. 8285 crores in 1986-87 which is as much as 127 per cent higher than the originally projected figure of Rs. 3650. In reality, the deficit would have even been higher had

[Shri Samar Mukherji]

the Centre not transferred something like Rs. 2500 crores to Rs. 3,000 crores from the oil industries surplus generated primarily by the drop in petrol prices earlier this fiscal year."

This is one reaction. Then, again I read THE HINDU. I am not going into details. In the editorial, the headline is: Floating in a sea of troubles.

"The public and the industry expecting a new thrust in Mr. Rajiv Gandhi's Budget have been treated to the spectacle of a Government floating on a sea of fiscal troubles."

Now, I want to analyse the policy of the Government and the actual reality. This is our criticism. We are making it not only now but we have been making criticism continuously about the basic policy of the Government because Government of India since independence is pursuing a basic policy of developing capitalism, strengthening capitalism in compromise with feudal forces in the villages as well as in collaboration with foreign imperialists, monopolists and that is why, in our country, the situation is heading towards such a position where the ultimate economic effect is, more and more unemployment which is ever increasing, poverty is also increasing and on the other hand, the big monopoly houses becoming far bigger. And the social impact is disruptive and parochial forces gradually coming on the top and it has reached a stage when secessionist forces have taken roots and they are killing innocent people deliberately with the slogan of Khalistan and division of India. Communal riots have greatly increased. If we do not go deeper into the causes of this turmoil, I think the present Government will completely fail to improve the situation in the country. The Government claims that it is a secular State, it is against comm' nal riots, it is for communal ami' and so on. We fully support this sentiment because we are fighting against communalism from the very beginning; we are fully behind the Government if the Government seriously undertakes the job of fighting secessionist and communal forces. But the way the Government is functioning, the way the ruling party compromises with communal forces for gaining advantage in elections, the way elections are conducted on caste basis, communal basis, the way huge amounts of money are spent, does not inspire confidence. They talk of secularism. Very good. But the practice is just the reverse. This is the contradiction this Government is *presently suffering from.* They are struggling to create an image by boosting their performance. But the reality is just the opposite. The farther the reality from their professions, the wider the gap between their claims and their achievements. Now the situation has gone out of control. Intervention in this situation will only come from below and that intervention has already started in Punjab. We had spoken repeatedly for a joint move. I had several times personally discussed with Prime Minister Indira Gandhi, "You mobile your forces; we are prepared to mobilise our forces; let us jointly mobilise the people against the secessionist forces in Punjab. Wherever there is a communal riot, you mobilise your forces and we mobilise our forces, not through State machinery, not through police, because police is vitiated by communal outlook, regional outlook." It has been admitted several times by Mrs. Indira Gandhi, by the then Home Minister who is now the President of India, on the floor of Lok Sabha. I was a Member of Lok Sabha for a long time. Repeatedly I raised this question on the floor of Lok Sabha and they admitted. When I met the Prime Minister separately in a closed-door meeting, she said, "My party is not like your party". This cannot be an explanation. That is why we welcome the move now started in Punjab. This is the move for which we repeatedly tried year after year. So, my

main criticism is against the outlook pursued by the Prime Minister and the Government, by the ruling party, regarding secularism, it is absolutely a wrong outlook. According to them the definition of secularism is encouraging all types of religions; daily you see on the TV the Prime Minister or the Rashtrapati or some ministers opening religious functions, our Ministers talking of secularism, encouraging religious functions and institutions. Their conception of secularism is "that we should accept all religions and try to combine them together, to maintain national unity". Repeatedly we told that secularism as a concept has a definite content. The State should be totally detached and separated from religion. But that never entered into the heads of the people of the ruling party and the Prime Minister particularly. Now the issue has come up. Just now my friend told that religion and politics should be separated. That is what we were demanding since long. Now things have reached a stage when the demand is coming from below also and it is a very welcome development which should be further carried forward. Informally I have told the Prime Minister, "You declare one day as the Punjab Day and you mobilise the forces in all the States against the communal forces and secessionist forces and mobilise all the secular forces". The time has come to take the initiative to fight this challenge. The Rashtrapati has told that it is a big challenge before the country. Certainly, it has become a challenge before the country. But we represent the working class, the toiling masses, and we know that it is much more dangerous to our joint struggles of the working class, of the peasanty, of the employees, etc. and that is why I say that you have to mobilise your forces against those communal and secessionist forces, and are confident that the working class will come into action throughout the country, throughout India, against these forces provided they get encouragement from the Government. But the situation is just the reverse. The Government is trying to repress and suppress all the trade union movements and all the working class movements. The working class is a class which is composed of all the linguistic nationalities, all the religious communities and of the toiling masses. Only through their joint struggles they can achieve some of their demands. But our task is to develop those struggles to a higher level so that they can come to the forefront to change the policies of the Government and unless that is done, sense will not enter into the heads of the ruling party and the Prime Minister that policies require a change.

Now, take the speech of the Rashtrapati. It is a fully complacent speech which says that the economy is advancing very soundly. Read the speech of the Prime Minister. In the superlative degree he has certified that the economy is very sound. Is it very sound? What about the question of employment? I will give you the figures. It is the 'Economic Survey' which has mentioned about the closure of factories, the sickness in the factories. I remember when I spoke on the President's Address in 1984, I gave the figures relating to sickness, industrial sickness. The number of sick units was 22,000 in 1982. Now, the 'Economic Survey' has said that this sickness has grown up to December 1985 to 1,19,000. Can you imagine? Factories are being closed and they are sick. The figure has risen from 22,000 to 1,19,000 up to December 1985. Take the period up to December 1986. There has been a further rise and another 15,000 to 20,000 sick units have been added to the list. One and a half lakh factories have been closed and sick and such huge numbers are sick within just two to three years. Is it the health of the economy? Is the economy sound? You say like that because you do not feel the effect of this closure. But will those thousands and thousands of workers who are thrown out of their jobs because of these closures accept your economy to be sound? Then what is

[Shri Samer Mukherjee]

the purpose of the economy? In profession, all our objective is to remove poverty and all our objective is to remove unemployment. But what is the situation in the employment field? I will give you now some more figures. They are not my figures, but they are the figures given by the "Economic Times". The Government is trying to misrepresent the situation through the Planning Commission that day by day, through the Five Year Plans, the percentage of the people living below the poverty line is being reduced. But another department of the Government, the Employment Exchanges, gives the figure to show that the registered number in the Employment Exchanges is rising phenomenally. According to the Employment Exchange figures. this number is now near about equal to 3 crores—2 crores and 62 lakhs. But the Seventh Plan document claims that the backlog of the unemployed in 1985 was only of the order of 9.2 millions as against 12 millions in 1980. This is the Planning Commission's claim. But, on the other hand, the data on the live registers of Employment Exchanges in the country indicates that as many as 26 million persons were jobless in 1985 as compared to only 16 millions in 1980. Thus, on the one hand, the Planning Commission claims that there has been a reduction in the number of the unemployed between 1980 and 1985; on the other hand, a diametrically opposite picture is painted by the Employment Exchange data. More important, even the Employment Exchange statistics are not complete, because the Employment Exchange gives only the number of the unemployed who are living in cities and towns, and they go and enter their names in the Employment Exchange. Vast sections of the unemployed who are in villages do not get their names registered in the Employment Exchange.

A measure was discussed during the Second Plan. That is mentioned here in the 'Economic Times'. Using the norms advanced in the Second Plan document that the actual unemployment in the country is four times the figure mentioned in the official Employment Exchange data, the estimate of the jobless now would be as high as 100 million, if not more. This is not my comment. This is what the Economic Times Research Bureau has stated. Now, the Economic Survey has mentioned that when this staggering figure of growth of unemployment is there, the potentiality for employment is being reduced. The population is growing. Factories are becoming sick. Where will the people go for jobs? The Government is claiming that they are developing this scope they are creating scope of employment in villages, in rural areas, where the agriculture is already overburdened with population and unemployment. The official statistics reveal that there were 26 lakh families which benefited by the major poverty alleviation schemes of IRDP. The 'Economic Survey' has mentioned how the growth potentiality of employment has been gradually reduced. The growth pattern of employment and fixed capital in the factory sector since the beginning of seventies reveal that while the rate of growth of fixed capital averaged 13.5 per cent in the seventies and early eighties, the rate of growth of employment was just 3.5 per cent. The fixed capital has therefore been growing almost four times faster than employment. In the Presidential speech this has been concealed. The reality is that employment potential is going down completely. What is the solution? Even the 'Economic Survey' has admitted that there is concern that non-plan expenditure is growing. The budget document pledges commitment to planning for socialism. In the budget speech as also in the Rashtrapati's speech, emphasis has been laid on removing poverty and unemployment. You will remember that the main slogan during 1970-71 parliamentary elections was garibi hatao. That was given by Mrs. Gandhi. It was the main election slogan. When we compute the consumer price index, the

base year is 1970-71. Base means 100. Now the wholesale price index has reached 389. That means that since that time till today, *i.e.* nearabout 16 years after the price has been constantly increasing. This is the index of the wholesale prices. The retail prices have far surpassed. Even this 'Economic Survey' has accepted that consumer price index is very much out of control and this is a source of great concern for the Government. So, if you say that the economic policy of the Government is very sound and it is advancing in a healthy way, we will contradict it at each stage because the increase in prices affects the common people. That is why we feel concerned about this policy. When the consumer price index increases further, it affects the workers, the peasantry and the common mass of people including middle-class people and all those people whose incomes are very limited. What is the remedy? There is no remedy because the attitude of the Government is complacent. I may point out the contradictions in this policy. In the Budget speech, the first quotation is from Pandit Jawaharlal Nehru. I quote:

> "The times we live in and the problems that our country has to face do not permit a static or complacent approach."

Here he quotes that there should not be any complacent approach. The whole budget speech and the speech of the President is showing complacency at a high level without going into the realities.

Then I come to the question of the solutions suggested for removing poverty and unemployment. What is the solution suggested? It is only modernisation. Anybody who has commonsense will know that introduction of modernisation in offices means replacement of labour. Machine takes the place of human labour. That is why the entire working class and the employees are worried because of this modernisation. Now modernisation is advancing throughout the world because science is advancing very rapidly. It is suggested that without modernisation India will lag behind other countries. But when there is huge backlog of unemployment and when 40 to 45 per cent of our peaple are living below the poverty line, there is need for creating more scope for employment. Modenisation in offices, factories and railways means further erosion of jobs. So. the contradiction between the lives of the people and the policies is bound to grow which will result in more and more agitations.

1.00 P.M. The Government's policy is more to invite the monopoly houses and privatisation. That is why on 21st January all the public sector employees including officers organised one-day protest strike. What was their demand? Their demand was a change of policy. The Government's policy is conflicting with the interest of the employees and the workers and the policy of self-reliance. The Government is handing over the entire economy to monopolies, particularly the multinational corporations. And these multinational corporations are the real leaders in the American Government, the military-industrial complex who are preparing for nuclear war. And this American imperialism is helping Pakistan with the most sophisticated arms and even helping to manufacture the atom bomb. You should not allow these Americans to penetrate into our economy. But the entire economic policy of the Government is to hand over our economy to them. The more you take loans from the IMF and the World Bank, the more you are to accept the conditionalities which they impose, that is why more surrender to the monopoly houses. And whenever they invest money, whenever they bring in any new technology, they are not helping us not without any interest. Their political interest is that from inside the economy should be dominated by them. And they will influence the

[Shri Samar Mukherjee]

internal policy as well as the foreign policy of the country. That is why we are very much worried about the internal policy pursued by the Government of India though we support the foreign policy of the Rajiv Government. And you know the imperialists role in helping the extremists and secessionists in Punjab. in Assam, in Tripura, and in various other States. The role of the American imperialism and the CIA is widely known now. From the very beginning we demanded that the Government must expose them. There is a mention of foreign help in Rashtrapati's speech. But there is no mention of America. That shows the lack of courage of the Government of India because of this monetary help and this policy of inviting more the multinational corporations. Now in the name of non-resident Indians you are inviting freely. And in his speech Rajiv admitted—I have no time to quote—that those who invest money, their interests should be guaranteed. What is that interest? Earning huge profits. At the cost of whom? The Indian people. And this price hike is not an isolated thing. It is a part of the total economic policy of the Government of India. That is why the price rise means they will earn huge profits by exploiting the masses. Your Government is giving tax concessions to the monopoly houses. (*Time bell rings*) I am concluding.

AN HON MEMBER: This is his maiden speech.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have got ten minutes more than the allotted time.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: I am discussing a serious question which concerns the future of millions of our people. So, the Government has given a guarantee that the investors' interest should be defended. This is out and out helping, building monopoly capitalism. But what is the profession? This is socialism. The most ridiculous thing has been spoken here. What is socialism? Socialism means social ownership of the entire means of production. There is no private owner in the Soviet Union, no big private owner in socialist countries. That is socialism. And in a socialist country, the technology can advance. The entire people can get the benefit at the advancement of technology only in a socialist system. Here the benefit of the advanced technology is being gained by the monopolists and the employers at the cost of employees and workers. That is why the question of improvement of technology introduction of modern technology should be combined with the establishment of real socialism. Real socialism means taking the ownership of the big monopoly houses into the hands of the Government led by the working class. Now, what are the workers demanding? The jute industry is in deep crisis. All unions, including the INTUC demand that the jute industry should be nationalised. Rajiv Gandhi went to Bengal. All unions met him and demanded you accept nationalisation. He said, no. Your policy is privatisation. Give more and more encouragement to private monopolists. Workers' demand is nationalisation, take over the ownership from these private hards. So, the interests are conflicting. Unless the alternative policy nationalisation combined with participation of workers in the management that is accepted, the industrial crisis, sickness, will further grow and increase and lakhs and lakhs of workers will be thrown out of jobs. There are other factors which are creating serious crisis.

Regarding agriculture, I have no time. I am shortening my speech. What is the position in the villages? Accordnig to the latest agriculutral census land held by top one per cent of the cultivating households is nearly equal to the area held by bottom 60 per cent of the cultivating households which does not include landless rural

population. There this disparity is so big, in the villages, the exploitation is increasing day by day but here the picture is being given that by your programmes, by poverty alleviation, the IRDP and other programmes, the unemployment is being reduced. That claim is absolutely baseless and it has no relations with actual realities. That is why it must be given serious thought and we think the policy changes will not come from the top because the way the Government is advertising the policies in superlative degrees, a bitter fight is going to come from the masses to change the present policies of the Government.

I am concluding now but before that I want to give one figure to answer their claim that in the villages they are having impact for this unemployment and poverty alleviation programmes. This is also the Government figure. The official statistics reveal that there were 26 lakh families which benefited by the major poverty alleviation scheme of the Integrated Rural Development Programme, IRDP, during 1985-86 as against the target of 40 lakh families. The evaluation of the programmes however, discloses that in 23 percent of the cases surveyed, there has been no increase in the income from assets provided, in 30 per cent of the cases the assets were not intact, i.e., either old, fully perished, partly perished or defective. So, these schemes which the Government has formulated are being used for the major benefit of some vested interests both in the villages as well as in the cities and a major part of the money goes into their pockets and those for whom thest schemes are meant they get much less benefit, because this is the main structure of our administration and our system here. Without basic land reforms poverty cannot be removed. The policy followed by our Prime Minister is that suddenly he goes to the villages, to the rural poor along with him with a television set and T.V. pictures taken to create an image genuinely as if he is interested to remove poverty. This is not the method to remove poverty, i.e. by suddenly visiting some poor people's houses and giving that a wide publicity in order to catch votes. This method will never solve the problems. The problem is very serious. The economy is in serious crisis and all types of contradictions are bound to grow and develop and in a national situation unless the toiling masses organise themselves and fight for changing this policy the Government will not realise the gravity of the situation.

Madam, I oppose this motion of thanks and I conclude by saying that serious thought is necessary not by the Government alone but by the entire people of this country regarding the policies pursued by this present Government.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीया उपसभापति महोदया, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री भुवनेश चतुर्वेदी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की आर्थिक, राजनैतिक नीतियों का जहां प्रतिबिम्ब दिखायी देता है वहीं देश की तरक्की के लिए एक वर्ष के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं उसका प्रारूप झलकता है। पिछले वष राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिन नीतियों तथा कार्यक्रमों का उल्लेख किया था मुझे यह कहते हुए बड़ा गौरव अनुभव हो रहा है कि वे सारी नीतियां और कार्यक्रम आज एक ठोस उपलब्धि के रूप में परिणित हो गई है और आने वाले कल के लिए हमारी आज की बुनियाद को इससे काफी मजबूत आधार मिला है।

नयी शिक्षा नीति आज पूरे देश में शुरू हो गई है। नये बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन से भारत में रहने वाले हर आम आदमी के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किये गये हैं।

[श्री सुरेश पचौरी]

औद्योगिक विकास में तेजी एवं निर्धनों की दशा में सुधार लाने के लिए तैयार किये गये तकनीकी मिशन ने बेरोजगारी पर सीधा प्रहार किया है। गंगा प्राधिकरण, बंजर भूमि का विकास, नई कपड़ा नीति, प्रशासनिक तंत्र में सुधार आदि क्षेत्रों में सरकार ने ठोस उपलब्धि और गौरव प्राप्त किया है। परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्वक उपयोग, पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदुषण की रोकथाम के लिए राजीव जी द्वारा किये गये प्रयासों को आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी और उसकी बड़ी कृतज्ञ रहेगी। महोदया, राष्ट्र की एकता और अखण्डता को चुनौती के रूप में स्वीकार कर राजीव जी ने एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया है और 20 अगस्त 1986 को भारत बनाओ का नारा दिया है। एक ऐसा भारत जिस में हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, एक ऐसा भारत जहां जात-पात या अमीर और गरीब में भेदभाव न हो एक ऐसा भारत जहां सर्व धर्म समभाव हो तथा जो शान्ति, सहिष्णुता के संदेश से वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को साकार कर सकें।

भारत मानव प्राणी को अपनी सम्पूर्ण प्रगति का मापदंड स्वीकार करता है। स्वाधीनता के पूर्व एक औसत भारतीय की आयु 32 वर्ष थी परन्तु आज उसकी जीवन अवधि 22 वर्ष और अधिक बढ़ गई है। 1951 में प्रति हजार व्यक्तियों पर मृत्यु दर 27.4 थी अब वह घट कर 10 प्रति हजार हो गई है। बहुत सी बीमारियों को भी खत्म कर दिया गया है। कई लोककल्याणकारी कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों को भी सम्बद्ध किया गया है जो कि एक अभिनन्दनीय प्रयास है। प्रति वर्ष साक्षरता का जो स्तर है वह काफी बढ़ रहा है। आज यह 38 प्रतिशत के लगभग है तो 1950 में मात्र 16 प्रतिशत था। 6 से 11 वर्ष की उम्र के 93.4 प्रतिशत बच्चे इन दिनों शिक्षा अध्ययन करते हैं जबकि तीन दशक पूर्व केवल 23 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते थे। गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई के कारगर हथियार के रूप में हमने नयी शिक्षा नीति लागू की है जो एक अभिनन्दनीय प्रयास है। अन्तर्राष्ट्रीय घटना-क्रमों में राजीव जी ने इसी नीति पर अक्षरशः अमल कर विश्व की जनता का ध्यान भारत की ओर खींचा है। पिछले दो वर्षों में राजीव जी ने यूरोप, अमरीका एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण प्रशांत देशों की महत्वपूर्ण एवं लाभदायी यात्राएं की हैं। हरारे में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन उनकी अध्यक्षता में हुआ, लंदन में संयोजित राष्ट्र मंडल के लघु शिखर सम्मेलन में भी दक्षिण अफ्रीका के बहिष्कार की भारत की मांग को उन्होंने मजबूती से प्रस्तुत किया। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष को राजीव जी ने जिस मजबूती के साथ उत्साहित किया है दुनिया ने उनके इस दृढ़ रवैये के लिए उन्हें बधाई दे कर के उनका अभिवादन किया है।

प्रिटोरिया सरकार के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध व अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के आंदोलन में समर्थन से वे विश्व भर में दलितों के मसीहा के रूप में उभरे हैं। अभी हाल में 8 जनवरी, 1987 को दक्षिण अफ्रीकी कांग्रेस के 75 वर्ष पूरे होने पर भारतीय युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित रंगभेद के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करके उन्होंने उपनिवेशवादी सरकार के दमन के खिलाफ संघर्ष में भारतीय जनता के योगदान को दोहराया है। अफ्रीकी कोष की स्थापना भी इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

श्री गोर्बाचोव की दिल्ली यात्रा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णायक कदम के रूप में साबित हुई है। राजीव जी ने दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर अहिंसा, न्याय तथा समता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों को नई संरचना प्रदान की है। पाकिस्तान द्वारा पंजाब के मामलों में दखलअंदाजी के सबूत एंव हमारी सीमाओं पर पाक फौजों के जमाव के बावजूद बातचीत जारी रखते हुये तनाव कम करने व सीधे संघर्ष को टालने की जिस कूटनीति का परिचय राजीव जी ने दिया है वह उनकी गहरी सूझबूझ का परिणाम है।

महोदया, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पाकिस्तान द्वारा बार बार घोषणा करने के बावजूद इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि पाक ने परमाणु बम बना लिया है। अभी दो मार्च के समाचार पत्रों में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डा० अब्दुर कदीर खान के कथन के अनुसार यह साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसके बारे में भारत सरकार को गम्भीरता से विचार करना बहुत जरूरी है।

राष्ट्र की एकता और अखंडता को देश की पूर्वांचल सीमाओं पर गम्भीर खतरों का सामना करना पड़ा है। पंजाब और आसाम समझौतों के माध्यम से राजीवजी ने शांति व सद्भाव की स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण किया है। पर्वतीय क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध राजीव जी ने वहां के लोगों, जनजातियों की पहचान बनाये रखने, उनकी सांस्कृतिक परम्परा को समृद्ध करने की ओर विशेष ध्यान दिया है। 20 फरवरी, 1987 को अरुणांचल और मिजोरम को पृथक राज्य का दर्जा प्रदान कर राष्ट्रीय मानचित्र में दो नये राज्यों के उदय का श्रेय राजीवजी को है। महोदया, गांधी जी ने कहा था कि यदि भारत को देखना है तो देश के गांवों में जाकर देखना होगा और यदि हम भारत के विकास की बात करते हैं, भारत की तरक्की चाहते हैं तो हमें गांवों की तरक्की करनी होगी। इस दृष्टि से मैं भारत में जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी ओर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो ध्यान आकर्षित किया गया है उसका उल्लेख करना चाहूंगा। सरकार ने पिछले वर्ष सभी क्षेत्रों में पीने के पानी, निरक्षरता को दूर करने, सभी बच्चों का रोगों से प्रतिरक्षण, तिलहनों और खाद्य तेलों के उत्पादन, बेहतर संचार व्यवस्था के लिए पांच तकनीकी मिशन कायम किये हैं। सामाजिक विकास की संभावनाओं को कार्यरूप में परिणत करते हुये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 में राज्य योजनाओं में 794.05 करोड़ रुपयों की राशि आवंटित की गयी है। इस कार्यक्रम के तहत 40 हजार गांवों के जोड़े जाने का प्रावधान है। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के तकनीकी मिशन ने *1989-90 तक 180 लाख* टन तिलहनो की पैदावार का कार्यक्रम चलाया है। इस दौरान इस पर 170 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह खाद्यान्न तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

गुलामी और गरीबी से संघर्ष का इतिहास कांग्रेस की विरासत है। 1971 में स्व० इंदिरागांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसी को आगे बढ़ाकर अमलीजामा पहनाने की दृष्टि से 20-सूत्री कार्यक्रम 1975 में उन्होंने घोषित किया था। देश की गरीब जनता के आर्थिक जीवन स्तर को सुधारने के लिए शुरू किया गया यह कार्यक्रम इंदिरा जी की देन है जिसे संशोधित करके हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने फिर 20 अगस्त 1986 को प्रस्तुत किया। गरीबी के खिलाफ संघर्ष में आई०आर०डी०पी० प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि 1984-85 में 207.7 करोड़ रु०, 1985-86 में 205.9 करोड़ रुपए और 1986-87 में 543.83 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दिसम्बर, 1986 के अन्त तक 20.7 लाख परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। इसी प्रकार जो एन०आर०ई०पी० प्रोग्राम है उसके अनुसार वर्ष 1984-85 में 230 करोड़ रुपये, 1985-86 में 337 21 करोड़ रुपये और 1986-87 में 479.75 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रगति में ग्रामीण विकास का एक बुनियादी महत्व है। इसी प्रकार भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम आर०एल०ई०जी०पी० में 1985-86 में 606.33 करोड़ रुपये के बदले 1986-87 में 731.10 करोड़ रूपये प्रस्तावित करना हमारे ग्रामीण विकास के मलभूत लक्ष्यों को महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बदलने का एक प्रतीक है।

गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में 65 प्रतिशत वृद्धि सरकार के गरीबी-हटाओ नारे का एक प्रतीक साबित होता है। महोदया, मान्यवर, सदस्य ने गरीबी की रेखा

[श्री सुरेश पचौरी]

और अनइम्पलायमेंट का जिक्र अभी हाल ही में किया। मैं एन०आई०आर०डी०, हैदराबाद द्वारा प्रकाशित जो पुस्तिका है, उसके द्वारा उनके कथन को असत्य निरूपित करना चाहूंगा। 1980–81 में टोटल जो आई०आर०डी०पी० बेनिफिशरी थे, वह 2.73 मिलियन थे, 1981–82 में 2.71 हुए, 1982-83 में 3.46 हुए और 1983-84 में 3.69 मिलियन हुए।

इसी प्रकार इम्पलायमेंट की जो बात उन्होंने की, इम्पलायमेंट जेनरेटिड, जो एन० आर०ई०पी० के तहत मिलियन मनडेज़ हैं, वह 1980–81 में 413.58 थे जबकि 1981–82 में 354.52, 1982–83 में 350.01 तथा 1983–84 में 302.7 मिलियन मेंनडेज़ थे। जो अभी हाल ही में जिस सदस्य ने यह जो बात की है, वह अपने आप इन आंकड़ों से असत्य साबित होता है।

इसी प्रकार पावर्टी रेशों और नम्बर आफ पीपल की जो उन्होंने बात की है, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जो पावर्टी रेशों 1977-78 में था, वह 48.3 प्रतिशत था और 1984–85 में 36.9 प्रतिशत, यह घट कर हो गया।

इसी प्रकार नम्बर आफ पुअर पर मिलियन 1977–78 में 306.8 था, यह घट कर 1984–85 में 272.7 हो गया यह आंकड़ें अपने आप में यह साबित करते हैं कि जो बात कही जा रही है कि गरीबी के खिलाफ संघर्ष करने में सरकार आशातीत सफलता अर्जित नहीं कर रही है, यह सारी बातें इन सदस्यों की अपने आप में गल्त साबित हो जाती हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का बड़ा महत्व है। सदियों से सूदखोर, महाजनों व सरमायेदारों के अर्थ-जाल में जकड़े ग्रामीण–भारत में बैंकों के देहातों में खुलने से सरकार के संवेदनशील रवैये से अपने जीवन में जहां ग्राम लोगों ने राहत महसूस की थी, विकास योजना के सफल क्रियान्वयन के मार्ग में भी बैंकिंग सेवाओं के योगदान की अपेक्षा की गई थी, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के बावजूद भी बैंक कर्मचारियों का दृष्टिकोण अभी तक बदल नहीं पाया है। वहां आज भी पूंजीवादी व्यवस्था देखने को मिलती है जिसमें कि परिवर्तन की आज महती आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात कि है कि बैंक कर्मियों की मानसिकता को बदला जाए ताकि वह अपनी स्थापना के मूलभूत आदर्शों व लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। बैंको का योगदान भारत में ग्रामीण विकास में हो सके क्योंकि हमारा देश महान है, लगभग जो अभी आंकड़े हैं, उसके हिसाब से भारत में 438 जिले हैं 5,096 ब्लाक हैं और जो रेवेन्यु रेकर्ड है, उसके हिसाब से 5,84,982 गांव हैं। इन सभी जगह राष्ट्रपति के अभिभाषण में वर्णित योजनाएं मूर्त रूप ले सकें उपलब्धियों के रूप में इनकी परिणति हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि हर भारतीय अपनी जवाबदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने कर्तव्य का सही निवर्हन करे क्योंकि प्रधान मंत्री राजीव जी के मन में यह भावना है कि भारत एक सम्मुनत देश बन सके, भारत की भी गिनती दुनिया के अंदर विकासशील देशों में हो सके, जिसके आधार पर यह कह सकें कि भारत इक्कसवीं सदी में एक समुन्नत भारत के रूप में प्रवेश कर रहा है। एक शायर द्वारा कहीं गई पंक्तियों के रूप में हमारे नेता, आदरणीय राजीव जी की भावना प्रतिबिंबित होती है और जो आम जनमानस से आम भारतीय से जो अपेक्षा करते हैं, वह झलकती है, जिसके अनुसार—

मैं चाहता हूं कि निज़ामे कुहन बदल डालूं
मगर फकत यह मेरे बस की बात नहीं,
उठो, बढ़ो ए दुनिया के आम इन्सानों,
यह सब की बात है, दो चार, दस की बात नहीं।

इन जजबातों के साथ, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हमारे साथी संसद् सदस्य आदरणीय श्री चतुर्वेदी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI RAMESHWAR THAKUR (Bihar): Madam Deputy Chairman, I deem it a privilege to support wholeheartedly the Motion of Thanks on the President's Address moved by

my esteemed friend, Shri Bhuvnesh Chaturvedi.

It is extremely gratifying that the President in his learned, thought-provoking and comprehensive Address running into 55 paragraphs has covered almost every significant aspect of our national life. In brief, the Address encompasses in it our firm commitment to the basic principles of democracy, secularism and socialism. It deals at length with the challenges, both external and internal, being boldly faced by the nation to its unity and integrity in Punjab and elsewhere in the country. It reaffirms our non-aligned foreign policy and objectives of peace, disarmament. development and cooperation with all nations for building an equitable world order. It mentions with pride the gains made and consolidation achieved during 1986 by thorough and comprehensive policy changes initiated by the Government under the dynamic leadership of the Prime Minister in several key areas of our social, economic and political fields.

The President's Address has drawn our attention to the main policy thrusts in his Address of last year and the positive results flowing on account of the bold and pragmatic action taken by the Government in the areas of revised 20-Point Programme, new education policy, technology mission, new orientation to agricultural policy, effective strategy for family planning, intensification of industrial growth, promotion of exports and tourism, reforms in the administrative system and electoral laws.

The President's Address highlights the important legislations passed by both Houses of Parliament in 1986, affecting important areas of changes in our national life, like the comprehensive environment protection legislation, legislation regarding consumer protection, legislation to improve the status of women, legislation in regard to the amendment of the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, amendment of the Dowry Prohibition Act and Indecent Representation of Women (Prohibition) Act.

The Address makes a comprehensive survey of major trends in our economy. It starts with convincing facts and figures: a growth rate of 5 per cent in gross national product during 1986-87, higher foodgrains production, remarkable performance of industrial infrastructure during the last two years—*i.e.* 9.5 per cent in power, 6 per cent in coal, 7.7 per cent in saleable steel, 8 per cent in railway freight and 16.5 per cent in fertilisers, satisfactory industrial production of 8.7 per cent in 1985-86 and about 7—8 per cent (expected) in 1986-87. Public sector investment has gone up by Rs. 14,347 crores in 1985-86 as compared to 1984-85 and it stood at Rs. 50,341 crores as on 4-1-86. There is greater emphasis on anti-poverty programmes—*i.e.* about 65 per cent rise in some of the major items. Exports grew by 17.3 per cent between April and November, 1986. Long-term fiscal policy has given an encouraging result in revenue generation. Similarly, the wholesale price index has been contained at reasonable limits, though the consumers price index is causing some concern.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the House stands adjourned for lunch and will meet again at 2.30 P.M. Mr. Rameshwar Thakur will continue thereafter.

The House then adjourned for lunch at thirty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, the Deputy Chairman in the Chair.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Madam Deputy Chairman. I was speaking about the industrial workers' contribution to raise production and productivity and finally the thrust of